

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-379

सोमवार, 24 जून, 2019/3 आषाढ, 1941 (शक)

रोजगार डाटा

379. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में रोजगार डाटा जारी किया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह सत्य है कि देश में पिछले वर्ष की तुलना में बेरोजगारी कई गुना बढ़ गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) रोजगार उपलब्ध कराने में पीछे चल रहे कौन से क्षेत्र हैं और जीएसटी और विमुद्रीकरण ने देश में रोजगार अवसरों को किस हद तक प्रभावित किया है;
- (घ) क्या सरकार के पास अगले तीन वर्षों के लिये देश में रोजगार सृजन में वृद्धि करने हेतु कोई योजना है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में और क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क एवं ख): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान एक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आयोजित किया गया था। सरकार द्वारा हाल ही में सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की गई है। सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, देश में सभी आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर नीचे दी गई है:

बेरोजगारी दर (% में)			
सर्वेक्षण वर्ष	पुरुष	महिला	व्यक्ति
2017-18* (पीएलएफएस)	6.2	5.7	6.1
2011-12 (एनएसएस 68वां दौर)	2.1	2.4	2.2
2009-10 (एनएसएस 66वां दौर)	2.0	2.3	2.0
2004-05 (एनएसएस 61वां दौर)	2.2	2.6	2.3

(टिप्पणी: *तुलना हेतु, पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है जिसके तहत सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन को तैयार किया गया है)

(ग): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वर्ष 2011-12 के दौरान रोजगार एवं बेरोजगारी पर तथा 2017-18 के दौरान पीएलएफएस पर श्रम बल सर्वेक्षण आयोजित किया। इन अवधियों के दौरान, प्रमुख क्षेत्रों द्वारा अनुमानित कार्यबल नीचे दिया गया है:

प्रमुख क्षेत्र द्वारा अनुमानित कार्यबल		
क्षेत्र	2011-12 (एनएसएस 68वां दौर)	2017-18* (पीएलएफएस)
प्राथमिक	48.9%	44.1%
द्वितीयक	24.3%	24.8%
तृतीयक	26.8%	31.1%

(टिप्पणी: *तुलना हेतु, पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है जिसके तहत सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन को तैयार किया गया है)

(घ एवं ङ) नियोजनीयता में सुधार करने के साथ-साथ रोजगार का सृजन करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के योग्य बनाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगा।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।
